Himalayan J. Soc. Sci. & Humanities, Vol 1 pp. 1-5, 2006 DOI: 10.51220/hjssh.v1i1.1

उत्तर भारत में ब्रिटिश काल में आपदा प्रबंधन एक अध्ययन

गिरधर सिंह नेगी एवं मंजुल जोशी
इतिहास विभाग डी० एस० बी० परिसर, कुमायूँ विश्वविद्यालय, नैनीताल, उत्तराखण्ड

प्राकृतिक आपदायें लम्बे समय से मानव समाज को भयावह रूप से प्रभावित करती रही हैं। सम्पूर्ण भारत वर्ष में उत्तर भारत का क्षेत्र प्राकृतिक आपदाओं से सर्वाधिक प्रभावित रहा है। ब्रिटिश काल में सम्पूर्ण उत्तर भारत ब्रिटिश शासन का केन्द्र बिन्दु था। ब्रिटिश काल में नगरों का विकास व वनों के तीव्र कटान के कारण हुए जलवायु सम्बंधी परिवर्तनों से प्राकृतिक आपदाओं में गुणात्मक वृद्धि हुयी। प्राकृतिक आपदाओं की इन परिस्थितियों से निपटने के लिये ब्रिटिश शासन ने आपदा प्रबंधन एवं न्यूनीकरण के विभिन्न कार्यक्रम उत्तर भारत में व्यापक स्तर पर चलाये थे। अपने इस शोध पत्र में हमनें ब्रिटिश शासन काल के दौरान उत्तर भारत में आपदा प्रबंधन के विस्तृत कार्यों का एक तथ्यपरक वर्णन किया है।

उत्तर भारत का एक परिचय-

उत्तर भारत से तात्पर्य भारतवर्ष के उत्तरी भाग से है जो कि हिमालय की तलहटी में शिवालिक श्रेणियों से गंगा-यमुना के विशाल दोआब तक विस्तृत है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 8 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक है। शिवालिक हिमालय का पर्वतीय भाग, उत्तर के मैदानी भाग में उपजाऊ गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र, उत्तर भारत में एक विशिष्ट जैव-विविधता युक्त परिक्षेत्र का निर्माण करते हैं।

विविधताओं से भरा हुआ यह उत्तर भारतीय क्षेत्र उत्कृष्ट जलवायु एवं उपजाऊ भूमि के कारण सम्पूर्ण भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। विशिष्ट भौगोलिक स्थिति व अधिक जनसंख्या के कारण यहाँ प्राकृतिक प्रकोप के दौरान क्षति की संभावना भी अधिक होती है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश, बिहार, आदि मुख्य रुप से उत्तर भारत के वे राज्य हैं जो कि लम्बे समय से प्राकृतिक आपदाओं से सर्वाधिक प्रभावित होते रहे हैं। क्षेत्र में मानसूनी जलवायु होने के कारण यहाँ वर्षा काल में बाढ़ की व्यापक संभावनायें बनी रहती हैं। इंडियन तथा यूरेशियन प्लेटों के मध्य स्थित होने के कारण यह सम्पूर्ण क्षेत्र भूकम्प की मार से सदा प्रभावित रहता है। पर्वतीय क्षेत्रों में चट्टानों के कमजोर होने से भूस्खलन का भय सर्वदा बना रहता है।

ब्रिटिश काल में उत्तर भारत में आने वाली प्रमुख प्राकृतिक आपदायें-

ब्रिटिश काल के दौरान सम्पूर्ण उत्तर भारत विविध प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित रहा जिनमें भूकम्प, भूस्खलन, बाढ़, सूखा एवं अकाल आदि प्रमुख प्राकृतिक आपदायें थी (तालिका-1)। हिमालय की शिवालिक श्रृंखला अवसादी चट्टानों से निर्मित है जिस कारण क्षेत्र में भूकम्प व भूस्खलन की गतिविधियाँ अधिक होती हैं।[1]

© SHARAD

22 मई 1803 ई0 को गोरखा राज के दौरान आये भयानक भूकम्प ने उत्तराखण्ड के सम्पूर्ण गढ़वाल परिक्षेत्र को व्यापक रूप से प्रभावित किया। भाद्रपद की अनन्त चतुर्दशी की आधी रात से निरंतर सात दिन-रात्रि तक आने वाले इस भूकम्प से गढ़वाल की मात्र 25% जनसंख्या ही जीवित रह पायी थी।[2]

वर्ष 1880 ई0 में नैनीताल में विनाशकारी भूस्खलन हुआ। इस घटना में 200 से भी अधिक लोगों की जाने गयी। तब नैनी झील का एक बड़ा हिस्सा मैदान में तब्दील हो गया था[3] इस घटना से सबक लेकर अंग्रेजों ने पहाड़ों के चारों ओर दर्जनों नाले बनवाये जो आज भी भू-कटान रोकने में सहायक सिद्ध हो रहे हैं। प्रसिद्ध इतिहासविद् एटकिंसन ने इस घटना का ब्योरा करते हुए लिखा है कि पूरा पहाड़ दलिये की तरह नीचे को बह रहा था जिसकी रफ्तार 2 कि0मी0 प्रति मिनट थी। इतनी तेज गति से एवलांश की तरह बढ़ रहे पहाड़ ने किसी को भी सॅभलने का मौका नहीं दिया[4]। 1883 में बिरही व नैनीताल में भूस्खलन के दस्तावेजी प्रमाण भी उपलब्ध हैं।

ब्रिटिश काल में उत्तर भारत में राहत व बचाव के कार्य-

ब्रिटिश काल में आपदा राहत एवं बचाव के कई अल्प एवं दीर्घ कालिक उपाय क्रियान्वित किये गये थे। तत्कालीन ब्रिटिश शासकों ने 1880 में नैनीताल में हुए भूस्खलन को गंभीरता से लिया। उन्होंने यहाँ निर्माण कार्यों के प्रति अत्यन्त सावधानी बरती तथा भारी व अनियन्त्रित निर्माण कार्य कभी नहीं होने दिये। उन्होंने नगर की पहाड़ियों में 79 कि0मी0 लम्बे नाले बनवाये जिससे कि वर्षा का पानी पहाड़ी का कटान किये बिना झील में समा जाय। अंग्रेजी शासकों ने लैंड स्लाइड मैनेजमैंट तथा हिल स्लोप स्टेबिलिटी के लिए इन पहाड़ियों में पौधारोपण करवाया तथा पहाड़ियों के खिसकने की रफ्तार नापने के लिए पिलर बनवाये साथ ही टैरेसिंग कम करके टैनिस कोर्ट मे बजरी बिछवाई।

तालिका-1: उत्तर भारत में आये विनाशकारी भूकम्पों की सूची -

क्रम संख्या	तिथि	स्थान	तीव्रता
1.	22.05.1803	उत्तरकाशी	6.0 परिमाण
2.	28.05.1816	गंगोत्री	7.0 परिणाम
3.	1833	बिहार	7.7 परिणाम
4.	14.05.1851	लोहाघाट	7.0 परिणाम
5.	25.10.1866	नैनीताल	6.0 परिणाम
6.	1905	हिमाचल प्रदेश	7.0 परिणाम
7.	1934	बिहार, नेपाल	8.3 परिणाम
8.	04.06.1945	अल्मोड़ा	6.5 परिणाम

उत्तर भारत का सम्पूर्ण क्षेत्र ब्रिटिश काल में भूकम्पीय आपदा से सर्वाधिक प्रभावित रहा। हिमालयी क्षेत्र में इंडियन तथा यूरेशियन प्लेटों की आपसी टकराहट की वहज से अपार उर्जा इकट्ठा होती रही है तथा प्रति वर्ष छोटे-छोटे भूकम्पों की शक्ल में उर्जा का अंश पृथ्वी से बाहर निकलता रहा है, परन्तु अपार ऊर्जा के कारण कभी-कभी भूकम्प का परिणाम बढ़ने से अत्यन्त विनाशकारी भूकम्प भी आये हैं।[5]

ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर भारत क्षेत्र का भीषणतम भूकम्प कॉगड़ा हिमाचल प्रदेश में 1905 ई0 में आया।[6] कॉगड़ा भूकम्प में राहत व बचाव कार्यों के क्रियान्वयन हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा कॉगड़ा भूकम्प राहत कोष की स्थापना की गयी।[7] लगभग 15000 लोग इस भूकम्प के दौरान मारे गये तथा भारी संख्या में पालतू पशु भी काल का ग्रास बने।[8]

धर्मशाला जिले के पुलिस अधीक्षक मि0 होमेन ने यथा शीघ्र शासन को आपदा के विषय में सूचित करके जीवित रह पाये लोगों के लिये चिकित्सकीय सहायता, टैन्ट, भोजन इत्यादि की मांग की।[9] इसके अतिरिक्त गोरखा रायफल्स के क्रनेल राबिन्सन ने भी पठानकोट को टेलीग्राम संदेश भेजकर शीघ्रातिशीघ्र सहायता की माँग की[10]

उत्तर भारत क्षेत्र का द्वितीय भीषणतम भूकम्प 1934 में बिहार-नेपाल में आया।[11] इसके अन्तर्गत सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र उत्तरी बिहार था जो कि भूकम्प का केन्द्र था। इस भूकम्प के दौरान 900 मील रेलवे रेलवे लाईन एवं लगभग 361 पुल क्षतिग्रस्त अथवा पूर्णतः नष्ट हो गये थे।[12] केवल मुजफ्फरपुर जिले में 2539 लोग मारे गये। दरभंगा में मृत लोगों की संख्या 2149 पहुंची थी[13]। मुजफ्फरपुर के उत्तर में स्थित सीतामढी एवं दरभंगा जिले के उत्तर में स्थित मधुबनी, दोनों ही सबडिवीजन भूकम्प से सर्वाधिक प्रभावित एवं दरभंगा जिले के उत्तर में स्थित मधुबनी, दोनों ही सबडिवीजन भूकम्प से सर्वाधिक प्रभावित रहे, यह क्षेत्र सम्पूर्ण भारत से एकदम अलग-थलग पड़ गया था। इन क्षेत्रों में शीघ्र ही कैम्प हास्पिटल खोल दिये गये तथा वस्तुओं की कीमतों में नियंत्रण के प्रभावी कदम उठाये गये[14]।

दरभंगा राजमहल तथा पुलिस लाइन में अतिशीघ्र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोल दिये गये तथा 16 तारीख तक पोलो ग्राउन्ड में कैम्प हास्पिटल बना दिया गया[15]। मोतीहारी जिला भूकम्प के बाद चार दिन तक सड़क, रेल मार्ग तथा टेलीग्राफ व्यवस्था से पूरी तरह कटा रहा। इस समय भोजन की कीमतें निश्चित करके उन्हें प्रकाशित भी करवा दिया गया[16]।

22 जनवरी को बिहार कांग्रेस के नेता बाबू राजेन्द्र प्रसाद ने सरकार से लिखित रूप में माँग की कि बिहार में एक गैर सरकारी संस्था "बिहार केन्द्रीय राहत समिति" के नाम से बनाई जाये जो कि भूकम्प प्रभावित क्षेत्रों में सहायता व राहत कार्य चलाये[17]। 1934 के भूकम्प ने क्षेत्रीय सरकार व कर्मचारियों पर भारी दबाव डाल दिया था। उन्हें क्षेत्र में राहत व बचाव सहायता के व्यापक कार्यक्रम चलाने पड़े। क्षेत्र में मूलभूत ढाँचे के व्यापक नुकसान से क्षेत्रीय राजस्व की व्यापक हानि हुई थी तथा

क्षेत्रीय सरकार भारत सरकार पर पूणतः निर्भर हो गई थी[18]।

उत्तर प्रदेश का पर्वतीय भाग वर्ष 1916 से 1930 तक लगातार वनाग्नि से प्रभावित रहा। इस काल में तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नर द्वारा विस्तृत कार्ययोजना तैयार की गयी परन्तु वनाग्नि पर नियंत्रण हेतु योजनायें प्रभावी सिद्ध न हो सकीं व लम्बे समय तक यह क्षेत्र वनाग्नि से प्रभावित बना रहा[19]।

ब्रिटिश काल के दौरान साधनों की कमी, यातायात संसाधनों के अभाव तथा प्रशासकीय निरुत्साह व अरुचि के कारण आपदा प्रबंधन व राहत एवं बचाव कार्यों में शिथिलता आयी तथा आपदा प्रबंधन का ढांचा प्रभावी ढंग से कार्य करने में अक्षम बना रहा। तथापि ब्रिटिश सरकार द्वारा कई स्थानों पर आपदा प्रबंधन बचाव व राहत कार्यों को व्यवस्थित ढंग से पूर्ण किया गया। नैनीताल में व्यवस्थित ढंग से नालों का निर्माण करवाना, बड़े निर्माण कार्यों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना, तथा आपदा न्यूनीकरण व प्रबंधन के क्षेत्र में ब्रिटिश सरकार का कार्य सराहनीय था। कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के भूकम्प के पश्चात् उपयुक्त बचाव व राहत कार्यों को चलाकर ब्रिटिश सरकार ने प्रभावी आपदा प्रबंधन ढ़ाँचे का परिचय दिया। अकाल आयोग का गठन कर व भविष्य में अकाल से सुरक्षित रखने की व्यवस्था इत्यादि में ब्रिटिश सरकार ने विशेष भूमिका निभाई।

ब्रिटिश काल में जनता का आर्थिक शोषण, देशी लघु एवं कुटीर उद्योगों का ह्रास, भारतीय धन का बहिर्गमन, कृषि की बिगड़ी हुई दशा व जमींदारों द्वारा गरीब किसानों का शोषण आदि कारणों ने जनता को अत्यधिक गरीब बना दिया। जनता की इस गरीबी की पराकाष्ठा अकालों की एक कड़ी के रूप में परिवर्तित हुई। इन अकालों ने उन्नीसवीं शताब्दि के अंतिम दशकों में भारत के समस्त भागों में भारी कहर बरपाया। इनमें प्रथम अकाल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 1860-61 में पड़ा था जिसमें दो लाख व्यक्ति मारे गये[20]। 1865-66 में अकाल ने उड़ीसा, बंगाल, बिहार, व मद्रास को धर दबोचा। इस अकाल के दौरान सम्पूर्ण भारत में बीस लाख लोग मारे गये। 1868-70 के अकाल में 14 लाख से भी अधिक लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मुंबई, एवं पंजाब में मारे गये[21]।

उस समय का सबसे भयानक अकाल 1976-78 में मद्रास, मैसूर, हैदराबाद, महाराष्ट्र, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पंजाब में पड़ा। उत्तर प्रदेश में इस अकाल के दौरान 12 लाख लोग मारे गये। 1896-97 और फिर 1899-1900 में देशव्यापी अकाल पड़ा। राहत व बचाव के व्यापक कार्य इस दौरान हुए परन्तु बचाव के विभिन्न सरकारी प्रयासों के बावजूद पच्चीस लाख से अधिक लोग इस अकाल के दौरान माने गये। एक ब्रिटिश लेखक विलियम डिग्बी ने ऑकलन किया कि 1854 से 1901 ई0 तक कुल मिलाकर 2,88,25,000 से अधिक लोग विभिन्न अकालों के दौरान सम्पूर्ण भारत में मारे गये।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आपदा प्रबंधन का महत्व-

क्षेत्र में तीव्र औद्योगिक विकास एवं शहरीकरण के कारण व्यापक रूप से जनसंख्या वृद्धि हुई है तथा वनों के तीव्र कटान, विभिन्न जलवायुवीय परिवर्तनों एवं मानवीय भूलों के कारण प्राकृतिक आपदाओं में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है जिसके कारण उत्तर भारतीय क्षेत्र में जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा

प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित रहता है। कुशल आपदा प्रबंधन के द्वारा ही वर्तमान समय में प्राकृतिक आपदाओं के दुष्प्रभावों को कम किया जा सकता है। आपदा न्यूनीकरण, आपदा पूर्व तैयारी, राहत व बचाव के कार्य, पुनर्वास व पुनर्स्थितिकरण, पूर्व चेतावनी व्यवस्था आदि आपदा प्रबंधन के प्रमुख घटक हैं जो कि जान-माल के भारी नुकसान को कम करने में सहायक हैं।

प्राकृतिक आपदाओं के बार-बार घटित होने से देश की अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव पड़ता है। भारत एक विकासशील देश है तथा यहाँ संसाधनों की सर्वदा कमी बनी रहती है। आपदाकालीन परिस्थितियों में देश के साधनों का एक मुख्य भाग राहत सहायता एवं पुर्नवास कार्यों में खर्च करना पड़ता है। वर्तमान परिवेश में आपदाओं के प्रति जनजागरुकता की बहुत आवश्यकता है जिससे कि भारत आर्थिक प्रगति कर विकास के मार्ग पर अग्रसर हो सके।

संदर्भ ग्रंथ-

1. अशोक कुमार राव हेम्माडी, 2004, नेशनल बुक ट्रस्ट, नई दिल्ली पृ.-60
2. बद्रीदत्त पाण्डे: कुमायुँ का इतिहास- 1900, श्री अल्मोड़ा बुक डिपो,
3. Encyclopedia Britannica, Deluxe Edition, 2005
4. एटकिंसन : हिमालयन गजेटियर : उत्तराखण्ड प्रकाशन, हिमालय संचेतना संस्थान आदिबद्री, चमोली
5. अशोक कुमार राव हेम्माडी, भूकम्प, 2004, उपरोक्त
6. No.-619 Report on Kangra Earthquake from Chief secretary of Punjab 1905, Home Department, National Archives of India, New Delhi. P.6
7. Ibid, p. 6
8. No.173 The Secretary, To The Government of India, Home Department 1905 , National Archives of India, New Delhi p.1
9. Ibid, p. 8
10. Ibid. p.7
11. No. 2628- P.R. Government of Bihar and Orissa, Political Department, National Archives of India, New Delhi p.1
12. Ibid., p.2
13. Ibid., p.4
14. Ibid., p.5
15. Ibid., p.7
16. Ibid, p.8
17. Ibid., p.11
18. Ibid, p.12
19. Manual on Natrual Disaster Management in India; N.C.D.M., (II PA) New Delhi 2000
20. विपिन चन्द्र: आधुनिक भारत, सरस्वती हाउस, नारायणा, नई दिल्ली-1976 पेज-156
21. उपरोक्त